VISION IAS

www.visionias.in

VISION IAS
06 SEP 2022
RECEIVED

GENERAL STUDIES (TEST CODE : 1839)

Name of Candidate	Sukh Ram		
Medium Eng./Hindi	Hindi	Registration Number	370763
Center	Jaipur	Date	06/09/2022

INDEX TABLE

Q. No.	Maximum Marks	Marks Obtained
1	10	
2	10	
3	10	
4	10	
5	10	
6	10	
7	10	
8	10	
9	10	
10	10	
11	15	
12	15	
13	15	
14	15	
15	15	
16	15	
17	15	
18	15	
19	15	
20	15	

Total Marks Obtained:

Remarks:

INSTRUCTIONS

1. Do furnish the appropriate details in the answer sheet (viz. Name, Registration Number and Test Code).
   उत्तर पुस्तिका में सूचनाएं भरना आवश्यक है (नाम, प्रश्न–पत्र कोड, विद्यार्थी क्रमांक आदि)।
2. There are **TWENTY** questions printed in **ENGLISH & HINDI**
   इसमें बीस प्रश्न हैं अंग्रेजी और हिन्दी में छपे हैं।
3. **All questions are compulsory.**
   सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
4. The number of marks carried by a question/part is indicated against it.
   प्रत्येक प्रश्न/भाग के अंक उसके सामने दिए गए हैं।
5. Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate, which must be stated clearly on the cover of this Question-Cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in medium other that the authorized one.
   प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहिए जिसका उल्लेख आपके प्रवेश पत्र में किया गया है और उस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न–सह–उत्तर (क्यूसीए) पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिए गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।
6. Word limit in questions, if specified, should be adhered to.
   प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिए।
7. Any page or portion of the page left blank in the Question-Cum-Answer Booklet must be clearly struck off.
   उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिए।

VisionIAS

EVALUATION INDICATORS

1. Contextual Competence
2. Content Competence
3. Language Competence
4. Introduction Competence
5. Structure - Presentation Competence
6. Conclusion Competence

Overall Macro Comments / feedback / suggestions on Answer Booklet:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

VisionIAS

All the Best

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

1. An independent umbrella body that brings the various central investigative agencies under one roof holds the key to shoring up their credibility. Discuss. **(150 words) 10**

एक स्वतंत्र अम्ब्रेला निकाय जो विभिन्न केंद्रीय जांच एजेंसियों को एक छत के नीचे लाता हो, उनकी विश्वसनीयता को बढ़ाने की कुंजी है। विवेचना कीजिए।

भारत में विभिन्न केन्द्रीय मामलों के अन्वेषण के लिये केन्द्रीय जाँच एजेंसियाँ - भ्रष्टाचार, अपराध, आर्थिक अपराध, राष्ट्रीय सुरक्षा आदि मुद्दों का अन्वेषण करती है

केन्द्रीय जाँच एजेंसियाँ।

(i) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI)

(ii) प्रवर्तन निदेशालय (ED) - राजस्व विभाग

(iii) नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB)

(iv) राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी (NIA) - गृह मंत्रालय

इनकी स्थिति.

a. पर्याप्त स्वायत्तता का अभाव

b. पिंजरे में बंद तोते की संज्ञा - माननीय सुप्रीम कोर्ट (CBI)

c. कार्यप्रणाली में समन्वय का अभाव

d. राजनीतिक हस्तक्षेप।

VisionIAS

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

स्वतंत्र अम्ब्रेला निकाय : केन्द्रीय अन्वेषण एजेंसियाँ

(i) सभी एजेंसियों में बेहतर समन्वय होगा।

(ii) कार्य प्रणाली में एकरूपता आएगी।

(iii) राजनीतिक हस्तक्षेप न हीं होगा।

(iv) पर्याप्त स्वायत्तता से विश्वसनीयता बढ़ेगी।

(v) राज्य-केन्द्र विवाद - CBI - सामान्य सहमति को लेकर कम होंगे।

(vi) राज्य भी अन्वेषण एजेंसियों की सहायता करेंगे।

(vii) भ्रष्टाचार, अपराध की प्रभावी इन्वेस्टीगेशन होगी।

(viii) नेता-अपराधी-पुलिस गठजोड़ को भी उजागर करने में केंद्रीय अन्वेषण एजेंसियाँ सहायक होगी

अतः एक स्वतंत्र अम्ब्रेला निकाय निम्नलिखित एजेंसियों की स्वायत्तता, विश्वसनीयता, प्रतिष्ठा को बढ़ाने में सहायक हो सकता है

VisionIAS

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

2. Discuss the significance of the Doctrines of Pith and Substance and Colourable Legislation with respect to Centre-state relations in India.

(150 words) 10

भारत में केंद्र-राज्य संबंधों के संदर्भ में तत्व एवं सार के सिद्धांत और छद्म (आभासी) विधायन के सिद्धांत के महत्व की विवेचना कीजिए।

भारतीय संविधान सहकारी संघवाद की भावना को प्रमोट करता है जिसके लिए अनुच्छेद 246 में शक्तियों का विभाजन (विधायन के संदर्भ में) किया गया है। संघ सूची पर संघ, राज्य सूची पर राज्य विधायिका कानून बनाती है।

तत्व एवं सार का सिद्धांत : केंद्र-राज्य संबंध

इस सिद्धांत के अनुसार केंद्र द्वारा राज्य सूची के विषय पर विधान निर्मित किया जा सकता है एवं यह अल्पसंख्यक ही होगा अर्थात् राज्य की विधायन शक्ति बरकरार रहती।

राज्य सूची के विषयों पर अन्तर्राष्ट्रीय संधियों के क्रियान्वयन, राष्ट्रपति शासन, आपातकाल व राज्यों के अनुरोध पर संसद कानून बनाती है।

VisionIAS

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

छद्म विधायन : संबंध

इसमें केन्द्र अप्रत्यक्ष रूप से राज्यसूची के विषयों पर कानून बनाती है। जैसे- अन्तर्राज्यीय नदियाँ व नदी घाटी संघ सूची का विषय है वहीं जल राज्य सूची का जिसमें केन्द्र ने जल संबंधी कानून भी बनाये है।

राज्यों का आक्षेप

i) केन्द्र इन सिद्धांतों की आड़ में नेशन बिल्डिंग, राष्ट्रीय सुरक्षा व आर्थिक विकास के नाम पर राज्य की शक्ति का अतिक्रमण करती है।

ii) समवर्ती सूची संबंधी विधायन में राज्यों से परामर्श नहीं की जाती।

iii) केन्द्र राज्य सूची के विषयों पर बने कानूनों को राज्यों पर थोपती है एवं सहकारी संघवाद के कमजोर करती है।

अतः सरदार पटेल ने संविधान सभा में कहा था कि केन्द्र-राज्य विवाद तो होंगे ही उन्हें सहकारी संघवाद की भावना से सुलझाना चाहिए।

VisionIAS

VISION IAS™

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

3. Do you agree with the view that there should be simultaneous elections to the Lok Sabha and the State Legislative Assemblies in India? Discuss with suitable arguments. **(150 words) 10**

क्या आप इस विचार से सहमत हैं कि भारत में लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के निर्वाचन एक साथ होने चाहिए? उपयुक्त तर्कों के साथ चर्चा कीजिए।

भारत में 1967 तक लोकसभा व राज्य सभा के निर्वाचन एक साथ होते थे वहीं अब नहीं। एक साथ निर्वाचन से तात्पर्य एक मतदाता एक ही समय लोकसभा व राज्य विधानसभा के उम्मीदवार को मत डाल सके।

भारत में एक साथ चुनाव

पक्ष में तर्क

(i) इससे समय व धन की बचत हो सकती है (ADR Report - Max LS - 100 करोड़ ₹ व्यय प्रति निर्वाचन क्षेत्र)

(ii) इससे विकास कार्य बाधित नहीं होंगे। आचार संहिता के कारण कार्य बाधित होते है (नीति आयोग - स्ट्रेटेजी फॉर न्यू इंडिया @ 75)

(iii) इससे सैन्य बलों का दक्षतापूर्ण उपयोग किया जा सकेगा।

VisionIAS

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

(iv) बार-बार चुनाव से जाति-धर्म - सांप्रदायिकता बढ़ती है जिसका निवारण हो सकेगा।

(v) राजनेता विधि निर्माण में पर्याप्त ध्यान दे सकेंगे।

(vi) राष्ट्रीय सुरक्षा को भी बल मिलेगा।

लेकिन कई चुनौतियाँ -

a. कुछ राज्यों के विरोध व किन राज्यों की विधानसभा के कार्यकाल छोटा किया जाये।

b. इससे क्षेत्रीय दलों व क्षेत्रीय मुद्दों को नुकसान होगा।

c. एक साथ व्यापक प्रशासनिक मशीनरी की आवश्यकता।

ऋत. दो चरणों में एक साथ लोकसभा व आधे राज्यों तथा दूसरे चरण में आधे राज्यों का निर्वाचन करवाया जा सकता है जिससे अधिक निष्पक्षता, स्वतंत्रता, दक्षता आएगी।

VisionIAS

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

4. Discuss the need for codification of parliamentary privileges in India, in light of the uncertainty and ambiguity around them. **(150 words) 10**
भारत में संसदीय विशेषाधिकारों के बारे में अनिश्चितता और अस्पष्टता के आलोक में, उनके संहिताकरण की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए।

भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकारों का उल्लेख अनुच्छेद - 105 में किया गया है।

भारत में संसदीय विशेषाधिकारों की स्थिति -

(i) कोई एकीकृत कानूनी प्रावधान नहीं

(ii) संसदीय परम्पराओं, न्यायिक निर्णयों पर आधारित।

(iii) कुछ भिन्न-2 संसदीय विधानों में उल्लेखित

(iv) 'संसदीय विशेषाधिकारों' को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है।

(v) संसदीय विशेषाधिकारों की अस्पष्टता तथा उनके उल्लंघन पर स्वेच्छाचारी निर्णय

(vi) संसदीय विशेषाधिकारों का दुरुपयोग।

VisionIAS

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

संसदीय विशेषाधिकारों के संहिताकरण की आवश्यकता:-

(a) इससे संसदीय विशेषाधिकारों की सुरक्षा हो सकेगी।

(b) संसदीय गरिमा को बढ़ावा मिलेगा।

(c) संहिताकरण से दुरुपयोग की संभावना को रोका जा सकेगा।

(d) संसदीय कार्यवाही को अधिक दक्ष, कुशल बनाया जा सकेगा।

(e) संसदों के अधिकारों व कर्तव्यों की रक्षा हो सकेगी।

अतः संसदीय कारण से संसदीय विशेषाधिकारों का संहिताकरण किया जाना चाहिए ताकि संसदीय प्रणाली को और मजबूत किया जा सके।

VisionIAS

VISION IAS™
Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

5. While the Civil Services Board can be a step forward in making the Indian bureaucracy more effective, it has its own issues which need to be addressed. Analyse. **(150 words) 10**

हालांकि, सिविल सेवा बोर्ड भारतीय नौकरशाही को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में एक अग्रणी कदम हो सकता है, लेकिन इसके अपने मुद्दे हैं जिन्हें हल करने की आवश्यकता है। विश्लेषण कीजिए।

भारत में संविधान के अनुच्छेद 312 के अनुसार प्रशासन के लिए 'अखिल भारतीय सेवा' का प्रावधान है जिसे 'स्टील फ्रेम' की संज्ञा दी जाती है।

→ सिविल सेवा बोर्ड :- नौकरशाही पर प्रभाव

(i) इससे नौकरशाही पर राजनीतिक हस्तक्षेप को कम किया जा सकता है (2nd ARC)

(ii) इससे नौकरशाही की दक्षता में सुधार हो सकता है (सुरेन्द्रनाथ समिति)

(iii) इससे अनुचित स्थानांतरण व गैर महत्वपूर्ण पद पर नौकरशाही के स्थानांतरण को रोका जा सकता है (होता समिति)

VisionIAS

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

→ सिविल सेवा बोर्ड से संबंधित मुद्दे -

a. इसके सदस्यों की राजनीतिक पूर्वाग्रह आधारित नियुक्ति।

b. पर्याप्त स्वायत्तता का अभाव

c. सदस्यों में नौकरशाह विशेष के प्रति पूर्वाग्रह

d. पर्याप्त जानकारी के अभाव में केवल ACR के आधार पर निर्णय।

इन मुद्दों को संबोधित करने के लिए

- इसकी स्वायत्तता पर बल, राजनीतिक आधार पर सदस्यों की नियुक्ति पर रोक व पर्याप्त जवाबदेही तय कर दक्षता बढ़ायी जानी चाहिए।

अत: सिविल सेवा बोर्ड को महत्वपूर्ण अधिकार, स्वायत्तता प्रदान कर इसका उपयोग किया जाना चाहिए।

VisionIAS

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

6. Highlight the potential of India Digital Ecosystem Architecture (IndEA) 2.0 in transforming the ecosystem of service delivery in India. **(150 words) 10**
भारत में सेवा वितरण के पारितंत्र को रूपांतरित करने में इंडिया डिजिटल इकोसिस्टम आर्किटेक्चर (IndEA) 2.0 की क्षमता पर प्रकाश डालिए।

भारत में सेवा वितरण प्रणाली में सरकार द्वारा नागरिकों को जनकल्याण के लिए प्रदान की जाने वाली सेवाएँ सम्मिलित हों।

→ भारत में सेवा वितरण पारितंत्र : स्थिति

(i) सेवाओं की दक्षतापूर्ण आपूर्ति का अभाव
(ii) सेवा वितरण पारितंत्र में भ्रष्टाचार, लीकेज,
(iii) सेवा वितरण में देरी, अकर्मण्यता आदि।

→ इण्डिया डिजिटल इकोसिस्टम आर्किटेक्चर (IndEA 2.0 की क्षमता –

(a) यह सेवा वितरण पारितंत्र को पूर्णतः डिजिटलीकरण करने पर बल देता है जो भ्रष्टाचार, लीकेज को कम करेगा।

VisionIAS

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

(b) यह सेवा वितरण पारितंत्र में वस्तुओं व सेवाओं की नियो-टैगिंग को दक्षतापूर्ण लागू करने का प्रयास करता है।

(c) सेवा वितरण पारितंत्र में ब्लॉकचेन व एरियल रोबोटिक्स को शामिल कर संपूर्ण सेवा-वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने का प्रावधान करता है।

(d) यह 'डिजिटली फ्रॉड डिटेक्शन इकोसिस्टम' को भी अडॉप्ट करता है जो भ्रष्टाचार पर लगाम लगायेगा।

(e) इसमें जवाबदेहिता हेतु e-मोड पर विशेष बल दिया गया है।

अतः लोकतांत्रिक अभिवृद्धि के लिए प्रभावी सेवा वितरण में IndEA 2.0 क्रांतिकारी कदम साबित हो सकता है।

VisionIAS

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

7. What is Civil Registration System? Highlight its importance and discuss the measures taken by the government to bring about improvements in it.

(150 words) 10

नागरिक पंजीकरण प्रणाली क्या है? इसके महत्व पर प्रकाश डालिए और इसमें सुधार करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों पर चर्चा कीजिए।

'नागरिक पंजीकरण प्रणाली' भारतीय जनता के शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यवसाय, रोग, उद्यम आदि के साथ जन्म, मृत्यु आदि का विवरण प्रदान करने प्रणाली है।

नागरिक पंजीकरण प्रणाली : महत्व

(i) दक्षतापूर्ण नीतियों व क्रियान्वयन - सरकार उपयुक्त डेटा की सहायता से नीतियों की गुणवत्ता को दक्ष बना सकती है

(ii) लक्षित योजनाओं व लाभार्थियों तक पहुँच में वृद्धि होगी।

(iii) स्वास्थ्य संबंधी रोगों के निदान के लिए विशेष सेंट्रीलाइज्ड रिसर्च को प्रमोट किया जा सकता है

VisionIAS

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

(iv) व्यवसाय, जन्म - मृत्यु संबंधी आंकड़ों से भारत की वस्तुस्थिति की जानकारी मिल सकती है।

इसमें सुधार के लिए सरकार के प्रयास

(a). सरकार ने इस प्रणाली को डिजिटाइज किया है।

(b) बायोमेट्रिक डेटा संकलन पर भी बल दिया जा रहा है।

(c) इसे और अधिक व्यापक व दक्ष बनाने के लिए ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी को शामिल किये जाने के प्रयास (NITI आयोग)

(d) प्रशिक्षण युक्त कर्मियों की सहायता से ऑनलाइन नागरिक पंजीकरण प्रणाली पर बल।

अतः लक्षित विकास व समावेशी विकास की दिशा में नागरिक पंजीकरण प्रणाली की दक्षता महत्वपूर्ण है।

VisionIAS

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

8. The Prohibition of Employment as Manual Scavengers and Their Rehabilitation Act, 2013, provides an effective mechanism for empowerment of the intended beneficiaries in the society. Critically discuss. **(150 words) 10**

हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध एवं उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 समाज में इच्छित लाभार्थियों के सशक्तीकरण के लिए एक प्रभावी तंत्र प्रदान करता है। समालोचनात्मक चर्चा कीजिए।

'राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग' के अनुसार भारत में 2000-2020 तक लगभग 2253 लोगों की मृत्यु हाथ से मैला उठाने व सीवेज सफाई में हुई है।

हाथ से मैला उठाने की प्रथा : 2013 का कानून

(i) इससे सामाजिक स्तर पर जागरूकता आई है।

(ii) NCRB की 2021 की रिपोर्ट - हाथ से मैला उठाने की प्रथा में 2017-19 तक में 9% की कमी आई है।

(iii) स्वच्छ भारत मिशन पर आधी रिपोर्ट के अनुसार सफाई कर्मियों को विशेष किट (ऑक्सीजन, यंत्र) प्रदान की जाने लगी है।

(iv) सामाजिक दृष्टि व सोच में बदलाव तथा शहरी

VisionIAS

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

आवासन तथा सामाजिक न्याय मंत्रालय के अनुसार कर्मियों को पुनर्वास प्रदान किया गया है।

लेकिन इस कानून की सफलता संदिग्ध भी है

(a) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग प्रतिवर्ष 100 से अधिक कर्मियों की मृत्यु हो जाती है

(b) मैला उठाने वालों को सामाजिक स्वीकृति नहीं मिल पाती।

(c) पुनर्वास की प्रक्रिया बेहद धीमी है।

(d) लाभार्थियों की पहचान से जुड़े कई मुद्दे।

(e) प्रशासनिक सक्रियता व सतर्कता का अभाव।

अतः इस कानून में पर्याप्त सुधार व सुदक्षतापूर्ण क्रियान्वयन से मानवीय गरिमा व SDG-6 को प्राप्त करने की दिशा में प्रयास किए जाने चाहिए।

VisionIAS

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

9. Discuss the reforms that must be undertaken to strengthen the World Trade Organisation in order to address the vulnerabilities in the present global trading system. **(150 words) 10**

वर्तमान वैश्विक व्यापार प्रणाली में विद्यमान कमियों को दूर करने के लिए विश्व व्यापार संगठन को सुदृढ़ करने हेतु उस पर किए जाने वाले सुधारों की विवेचना कीजिए।

विश्व व्यापार संगठन पूर्व के GATT का उत्तराधिकारी है तथा उरुग्वे दौर की वार्ता के बाद 1995 में WTO की स्थापना की गई जिसमें भारत संस्थापक सदस्य है।

विश्व व्यापार संगठन के कार्य

(i) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रमोट करना

(ii) व्यापार में ट्रेड बैरियर, नॉन टेक्नीकल ट्रेड बैरियर को दूर करना।

WTO की अक्षमता: वैश्विक व्यापार प्रणाली में कमियाँ

a. चीन-USA का ट्रेड वार

b. इसकी डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी व अपीलीय निकाय निष्क्रिय।

c. पक्षपातीय नीतियाँ जो व्यापार विचलन पैदा करती है

VisionIAS

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

WTO को सुदृढ़ करने के लिए उपाय

(i) इसकी स्वायत्तता को शब्द प्रमोट करें
Eg- USA का डोमिनेंस।

(ii) विवाद निपटान निकाय व अपीलीय निकाय में सदस्यों की त्वरित नियुक्ति। (पिछले तीन वर्ष से खाली)

(iii) इसके निर्णयों को क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रों का सहयोग अनिवार्य कर लें।

(iv) इसकी कार्य प्रणाली व मशीनरी के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता।

(v) इसकी निष्पक्षता के लिए -यू चार्टर अडॉप्ट किया जा सकता है

अतः WTO को प्रासंगिक बनाये रखने के लिए सदस्य देशों को अति सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए।

VisionIAS

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

10. State the significance of the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). Also, discuss the need for a legally binding Marine Biodiversity of Areas Beyond National Jurisdiction (BBNJ) agreement.

(150 words) 10

संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि (UNCLOS) के महत्व का उल्लेख कीजिए। साथ ही, कानूनी रूप से बाध्यकारी राष्ट्रीय अधिकार से परे क्षेत्रों की समुद्री जैव विविधता (BBNJ) समझौते की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए।

संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि (UNCLOS)

समुद्री क्षेत्र में राष्ट्रों के अधिकार व दायित्वों को परिभाषित करने वाली संधि है। भारत ने इसे 1982 में sign किया।

UNCLOS : महत्व

(i) आधार रेखा से समुद्री क्षेत्र में घरेलू सीमा का निर्धारण करती है।

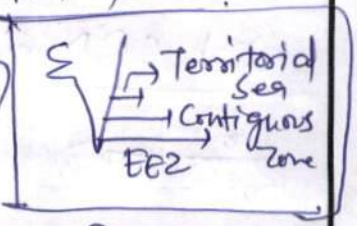

(ii) यह सामुद्रिक खनन के लिए अधिकार देती है - इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी - भारत को हिन्द महासागर में पॉली मेटालिक नॉड्यूल के लिए अधिकार मिले।

(iii) यह सामुद्रिक विवादों के भी निपटान

VisionIAS

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

जैसे चीन - फिलीपींस पर 2016 में निर्णय

समुद्री जैव विविधता समझौते की आवश्यकता

(i) सामुद्रिक (High Sea) के जीवों की रक्षा के लिए।

(ii) सामुद्रिक क्षेत्रों में अतिमत्स्यन को विनियमित करने के लिए

(iii) उच्च समुद्र में राष्ट्रों के मध्य विवादों के निपटारे के लिए।

(iv) UN CBD व UNEP की कन्वेंशन के साथ सुसंगतता के लिए

(v) जैव विविधता के संरक्षण व संवर्द्धन के लिए।

अतः UNCLOS, व समुद्री जैव विविधता समझौते पर बल देकर अन्तर्राष्ट्रीय शांति के प्रयास किये जाने चाहिए।

VisionIAS

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

11. Critically assess the role played by the National Human Rights Commission as a watchdog of human rights violations in India. **(250 words) 15**
भारत में मानवाधिकारों के उल्लंघन के प्रहरी के रूप में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा निभाई गई भूमिका का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए।

मानवाधिकारों से तात्पर्य समाज द्वारा स्वीकृत व विधि द्वारा अनुमोदित नागरिकों के दावों से है। मानवाधिकार प्रत्येक मानव को मानव होने के नाते प्राप्त होते हैं। 1946 में मानवाधिकारों पर 'सार्वभौमिक घोषणा' के प्रतिबद्धता के कारण NHRC का गठन किया गया।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग : स्थिति

↳ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधि. 1993
↳ एक वैधानिक निकाय
↳ सुप्रीम कोर्ट का जज या H.C. का मुख्य न्यायाधीश इसका अध्यक्ष होता है
↳ मानवाधिकारों की रक्षा करना तथा हर प्रकार के उल्लंघन का शमन इसका मोटिव है

VisionIAS

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

मानवाधिकारों के उल्लंघन के प्रहरी के रूप में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग –

(i) यह बंधुआ मजदूर, जबरन, ज्यादतियों व बलात श्रम से जुड़े मुद्दों पर निर्णय देता है

(ii) यह मानवाधिकारों के प्रहरी के रूप में उनकी रक्षा के लिए सरकार को रिपोर्ट करता है

(iii) यह जेलों का अचानक निरीक्षण कर जेल कैदियों की दशा में सुधार के लिए विभिन्न राज्य सरकारों को रिपोर्ट सौंपता है

(iv) यह मानवीय गरिमा व अधिकारों को न्यून करने वाले कृत्यों पर आरोपितों को समन करता है

(v) यह अपने सिविल कोर्ट की शक्ति का प्रयोग मानवाधिकारों की रक्षा के लिए करता है

(vi) यह निगरानी करके विभिन्न निकायों के कार्यस्थलों का त्वरित निरीक्षण भी करता है

VisionIAS

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

लेकिन NMRC मानवाधिकारों का सक्षम प्रहरी बनकर नहीं उभर सका है -

(a) इसकी सिफारिशों पर सरकार कोई एक्शन नहीं लेती।

(b) इसकी सिफारिशें बाध्यकारी प्रकृति की नहीं होती।

(c) इसके अध्यक्ष की नियुक्ति में अनावश्यक देरी की जाती है।

(d) राजनीतिक हस्तक्षेप से इसकी स्वायत्तता छिन जाती है।

(e) इसकी प्रशासनिक मशीनरी भी पर्याप्त नहीं है।

अतः मानवाधिकारों की रक्षा के लिए NMRC में पर्याप्त सुधार करके संवैधानिक नैतिकता को बढ़ावा दिये जाने का 'केन्द्र - राज्य - NMRC - SHRC' के स्तर पर प्रयास होना चाहिए।

VisionIAS

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

12. Discuss how the integration of information and communications technology (ICT) in the dispute resolution processes will help in overcoming the challenges associated with the functioning of courts and Alternative Dispute Resolution (ADR) forums. **(250 words) 15**

विवेचना कीजिए कि विवाद समाधान प्रक्रियाओं में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) का एकीकरण अदालतों एवं वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) मंचों के कामकाज से जुड़ी चुनौतियों का समाधान करने में किस प्रकार सहायता करेगा।

वैकल्पिक विवाद प्रणाली से आशय न्याया लय से बाहर मीडिएशन, आर्बिट्रेशन, सुलह, लोक अदालती प्रक्रिया से विवादों का समाधान करना है। भारत में नेशनल ज्यूडिशल डेटा ग्रिड के अनुसार 4.3 करोड़ मामले विचाराधीन है।

अदालतों व वैकल्पिक विवाद निपटान मंचो में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी —

इन मंचों की चुनौतियाँ

(i) डिजिटली का अभाव

(ii) आरोपी व गवाह की एक साथ उपस्थिति का अभाव

VisionIAS

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

(iii) पर्याप्त प्रशासनिक मशीनरी का अभाव

(iv) आवश्यक न्यायिक अवसंरचना का अभाव।

इसके निवारण में ICT

(a) यह लोक अदालतों व ADR में न्यायिक अवसंरचना को दुरुस्त कर सकता है

(b) ICT से वीडियो कान्फ्रेंसिंग से आरोपी व गवाह से पूछताछ की जा सकती है

(c) यह टेली जस्टिस की अवधारणा पर बल देकर न्यायिक देरी को समाप्त कर सकता है

(d) यह ब्लॉकचेन के माध्यम से न्यायिक रिकॉर्ड को बनाये रख सकता है

(e) कृत्रिम बुद्धिमत्ता से समान प्रकृति के मामलों का वर्गीकरण कर समय की बचत व प्रशासनिक बोझ कम कर सकता है

VisionIAS

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

(f) ICT से ADR व लोक अदालतों की जवाबदेही बढ़ सकती है।

(g) इससे दक्षतापूर्ण, त्वरित न्याय तथा कागजी प्रणाली को दूर कर डिजिटाइजेशन को बल दिया जा सकेगा।

ICT प्रणाली में विद्यमान चुनौतियाँ

→ गोपनीयता, डेटा सुरक्षा, इंटरनेट तक पहुँच, डिजिटल डिवाइड की समस्या।

→ डिजिटल साक्षरता मात्र 43% (NITI आयोग)

अतः मलिमथ समिति ने भी सिफारिश की कि ADR व लोक अदालतों में ICT का समावेशन इनकी दक्षता, कुशलता को सुधार करके न्यायिक प्रणाली पर बोझ कम कर भारतीय प्रजातांत्रिक न्यायिक प्रणाली को सुदृढ़ किया जा सकता है।

VisionIAS

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

13. Despite various provisions concerning disqualification of legislators under The Representation of The People Act, 1951, the issue of criminalization of politics is still unresolved to a large extent in India. Discuss.

(250 words) 15

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत विधायकों की निरर्हता से संबंधित विभिन्न प्रावधानों के बावजूद, भारत में राजनीति के अपराधीकरण का मुद्दा अभी भी काफी हद तक अनसुलझा है। विवेचना कीजिए।

भारत में 'एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म' (ADR) की हालिया रिपोर्ट के अनुसार 17th लोकसभा में 43% सांसदों ~~का~~ अपराधिक पृष्ठभूमि के है जिसमें से 29% पर जघन्य अपराध के मामले चल रहे हैं।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम: 1951 निरर्हता

→ अपराधिक विधायकों पर निरसन

→ निरर्हता का निर्णय चुनाव आयोग की सिफारिश के बाद राष्ट्रपति लेगा।

→ सुप्रीम कोर्ट ने लिलि थॉमस वाद में 2 साल या अधिक की सजा वाले विधायक को त्वरित ~~निरर्हता~~ अयोग्य करार देने का निर्णय दिया।

VisionIAS

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

फिर भी राजनीति का अपराधीकरण जारी है -

(a) पार्टियों द्वारा धनबल व बाहुबल के आधार पर टिकट वितरण

(b) केवल विनिंग फैक्टर पर बल

(c) अपराधियों की समाज में स्वीकृति

(d) राजनीतिक दलों में जवाबदेयता का अभाव

(e) अपराधीकरण को रोकने के लिए कानून का अभाव

(f) पर्याप्त संवेदनशील, गंभीर सरकार का अभाव

(g) न्यायिक प्रतिबद्धता व न्यायिक निर्णयों का क्रियान्वयन का अभाव।

इसका परिणाम

लोकसभा	अपराधीकरण
14वीं	24%
15वीं	30%
16वीं	34%
17वीं	43% (ADR Data)

VisionIAS

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

अपराधीकरण को रोकने के लिए

(i) प्रभावी कानूनों का क्रियान्वयन

(ii) न्यायिक निर्णयों को लागू किया जाना

(iii) मामलों के त्वरित निपटान के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का निर्माण (सुप्रीम कोर्ट निर्णय)

(iv) राजनीतिक दलों को RTI में लाना।

(v) नेताओं के लिए आचार संहिता, नैतिक संहिता

(vi) मिथ्या शपथ पत्र पर निरर्हता को लागू करना

(vii) भारतीय चुनाव आयोग को पर्याप्त शक्तियाँ देना।

(viii) जनता को जागरूक कर अपराधियों को नकारना।

(ix) अपराधीकरण के दुष्प्रभाव का प्रकाशन।

अतः लोकतंत्र को सुदृढ़, समावेशी व विश्वसनीय बनाने के लिए राजनीति के अपराधीकरण को रोकना अत्यंत आवश्यक है।

VisionIAS

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

14. It is time for reforms, which recognise that urban local bodies (ULBs) need permanent, buoyant revenue sources to match the growing demands of an increasing urban population. Discuss. **(250 words) 15**

यह सुधारों का समय है जो यह पहचान करता है कि शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) को बढ़ती शहरी आबादी की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए स्थायी, वृद्धिशील राजस्व स्रोतों की आवश्यकता है। विवेचना कीजिए।

भारत में स्थानीय स्वशासन पद्धति के लिए 74वां संविधान संशोधन किया गया। गठित शहरी स्थानीय निकायों का उद्देश्य शहरी जनसंख्या का कल्याण, शहरी अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण व जन सुविधाएँ प्रदान करना था।

भारत में ULBs समस्याएँ.

(i) भारत की 33% आबादी शहरी, UN अर्बन एजेंडा – 2030 तक 40% आबादी शहरों में होगी

(ii) अराजक यातायात, जल अपक्षय, झुग्गी बस्तियाँ।

(iii) शहरी सार्वजनिक सेवा वितरण में अकुशलता

विश्व बैंक - 25% शहरी आबादी स्वच्छ जल से वंचित है

(iv) शहरी अवसंरचना का अभाव

VisionIAS

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

v) शहरी स्थानीय निकायों के राजस्व स्रोत

(i) A-280 - केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा प्रदत्त अनुदान।

(ii) A-243I - राज्य वित्त आयोग गठित

(iii) राज्यों से उधारी, म्यूनिसिपल बॉन्ड।

(iv) संपत्ति कर, शुल्क आदि के राजस्व

नीति आयोग - ULBs के कुल राजस्व में मात्र 43% राजस्व स्वयं का होता है।

ULB - स्थायी, वृद्धिशील राजस्व स्रोत

(i) GST संरचना में सुधार कर GST राजस्व संग्रह का 2% ULB को प्रत्यक्ष हस्तांतरण हो।

(ii) राज्य खनिज रॉयल्टी में निश्चित अंश ULBs को दे।

(iii) ULB को संपत्ति कर वसूलने के लिए प्रेरित किया जाये। OECD Data - भारतीय ULB के कुल राजस्व में वेल्थ टैक्स का हिस्सा मात्र 0.15% है वहीं विकसित देशों में - 12-13%।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

(iv) ULBs की कर संरचना में पर्याप्त सुधार तथा राज्य कर शक्तियाँ प्रदान करें। जैसे शुल्क, चार्जेज वसूलने की क्षमता

(v) नीति आयोग 2.0 का गठन कर कमजोर ULBs को सशक्त बनाया जाये।

(vi) राज्य 'राज्य वित्त आयोगों' का समयपर गठन व उचित हस्तांतरण दें।

(vii) स्कैन्डेवियन कंट्रीज मॉडल - जिसमें आय कर पूल का निश्चित हिस्सा ULBs को दिया जाता है इसे लागू किया जाये।

(viii) अवसंरचनात्मक विकास के लिए ULBs को म्यूनिसिपल बॉण्ड जारी करने के लिए राज्य सहयोग करे।

अतः ULBs की वित्तीय स्थिति को उन्नत करने के लिए त्रिस्तरीय स्तर के सुधार लाये जाये ताकि स्वशासन व जनकल्याण को प्रमोट किया जा सके।

VisionIAS

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

15. The role of the civil society organisations (CSOs) in India is changing in contemporary times and has become increasingly more complex. Discuss.

(250 words) 15

समकालीन समय में भारत में नागरिक समाज संगठनों (CSOs) की भूमिका बदल रही है और निरंतर अधिक जटिल होती जा रही है। चर्चा कीजिए।

गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार

भारत में लगभग 33 लाख नागरिक समाज संगठन है जिसमें से मात्र 10% CSO सरकार को नियमित रिपोर्ट करते है।

भारत मे CSO का गठन भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, FCRA आदि के तहत किया जाता है।

a) CSO की बदलती भूमिका

i) इनकी प्रकृति में बदलाव - ये अब शिक्षा में उन्नत टेक्नोलॉजी के साथ विकास को गति प्रदान कर रहे है।

ii) सरकारी नीतियों को प्रभावित करने की व्यापक क्षमता - भारत किसान यूनियन आदि

VisionIAS

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

कृषि बिलों को वापस लेने का दबाव।

(iii) इनकी प्रक्रियाओं में विसंगतियाँ- कई संगठनों में से कुछ प्रशासनिक भ्रष्टाचार में लिप्त पाये गये हैं।

(iv) स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांति- Ketto, मिलाप, गिव इण्डिया, डोनेट कार्ट, इम्पैक्ट गुरु, SMILE फाउण्डेशन आदि स्वास्थ्य में क्राउडफंडिंग द्वारा गरीबों की सहायता कर रहे हैं।

(v) NIRAMAI हेल्थ एनालिटिक्स व InnAccel महिला स्वास्थ्य पर विशेष बल दे रहे हैं।

(vi) ये CSO रोजगार प्रदान के लिए भी अपनी नवीन भूमिका निभा रहे हैं।

(vii) इनकी गतिविधियों से सामाजिक न्याय व नीति निर्माण में सहयोग- NGO- प्रथम- ASER Report, Help Age इण्डिया आदि।

VisionIAS

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

→ CSO की भूमिका की जटिलता -

(i) विकास कार्यों में बाधा - कुछ NGO विकास को हानि पहुँचाते है (IB Report - GDP का 2-3% तक।

(ii) पर्यावरणीय मुद्दों के आधार पर 'इज ऑफ लिविंग' को बाधित करते है।

(iii) विदेशी अनुदान को भारतीय हितों के विरुद्ध प्रयोग किया जाना।
Eg. एमनेस्टी इंटरनेशनल पर आरोप

(iv) ये धोखाधड़ी, अनुदान के धन का दुरुपयोग भी करते है।

(v) इनमें से अधिकांश सरकार व प्रशासन की कार्यप्रणाली के विरोधी है।

अतः एक जीवंत सिविल सोसायटी संगठन डेमोक्रेसी का 5th स्तंभ होता है जिसकी भूमिका CSO को निभानी चाहिए।

VisionIAS

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

16. Though the Members of Parliament Local Area Development Scheme (MPLADS) aims to address the inequity in development in India, there are a number of issues which plague the scheme. Discuss. **(250 words) 15**
हालांकि संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीएलएडीएस) का उद्देश्य भारत में विकास में असमता से निपटना है, लेकिन ऐसे कई मुद्दे हैं जो इस योजना को प्रभावित करते हैं। विवेचना कीजिए।

भारत में विकासगत असमानता को दूर करने के लिए 1993 में संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLADS) लाई गई जिसमें वर्तमान स्वीकृत राशि 5 करोड़ प्रतिवर्ष है।

MPLADS उद्देश्य

(i) विकास में संतुलन लाना - भारत में कुछ क्षेत्रों यथा बिहार, झारखण्ड, ओडिशा में पिछड़ापन लम्बे समय से था लेकिन एक संसदीय निर्वाचन के भीतर ही विकासगत असमानता को दूर करने के लिए इसका गठन किया गया।

(ii) अनुसूचित जाति व जनजाति का कल्याण - MPLADS के तहत सांसद को SC/ST

VisionIAS

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

के विकास के लिए कुल राशि का 25% स्वीकृत करने की छूट हो।

(iii) सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए - दिव्यांगों के लिए 5% राशि का प्रयोग।

(iv) जिले के विशेष कस्बे का संतुलित विकास सुनिश्चित करने के लिए।

लेकिन MPLADS से जुड़े मुद्दे

(a) राशि का पूर्ण व्यय न हो पाना - संसदीय समिति की रिपोर्ट - 50% MP भी राशि का पूर्ण व्यय नहीं कर पाते।

(b) कार्यपालकीय ~~विवाद~~ विवाद - प्रशासन के पास स्वीकृति की शक्ति होती है तथा प्रशासक व MP के मध्य विवाद।

(c) असमान व अप्रासंगिक व्यय - MP द्वारा कुछ विशेष क्षेत्रों में अवसंरचना का

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

पक्षपाती विकास।

(a) अधूरी अवसंरचना - समय पर पूरी राशि के अभाव में अधूरी अवसंरचनाएँ वर्षों तक पड़ी रहती है।

(b) सांसदों की निष्क्रियता - सांसदों में सक्रियता का अभाव MPLADS का महत्वपूर्ण मुद्दा

सुझाव व सुधार

(i) MPLADS को पुनर्संरचित कर प्रभावी कार्यान्वयन के लिए ढाँचा बनाया जाये।

(ii) प्रशासन व MP/MLA की जवाबदेही तय हो।

(iii) विकास कार्यों की सैटेलाइट निगरानी हो।

(iv) विकास के लिए व्यय का सोशल ऑडिटिंग

अतः MPLADS को प्रभावी बनाकर विकासगत असमानता को दूर कर ~~समा~~ समावेशी व समृद्ध भारत का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है।

VisionIAS

VISION IAS™

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

17. Highlighting the factors responsible for the growth of EdTech sector in India in recent times, discuss its benefits. Also, state the concerns associated with it. **(250 words) 15**

हाल के दिनों में भारत में एडटेक क्षेत्रक के विकास के लिए उत्तरदायी कारकों पर प्रकाश डालते हुए, इसके लाभों पर चर्चा कीजिए। साथ ही, इससे जुड़ी चिंताओं का भी उल्लेख कीजिए।

नीति आयोग के अनुसार भारत में विगत तीन वर्षों में एडटेक क्षेत्र में 43-45% की वृद्धि हुई है तथा यह सनराइज सेक्टर बन चुका है।

→ भारत में एडटेक क्षेत्रक विकास के कारण

(i) Covid-19 - कोविड से संक्रमण व पारंपरिक क्लास प्रणाली का छूट जाना।

(ii) घटता डिजिटल डिवाइड - IAMAI की 'डिजिटल इन इण्डिया' रिपोर्ट के अनुसार भारत में शहरी क्षेत्र में 97.5% व ग्रामीण क्षेत्र की 55% इंटरनेट तक पहुँच।

(iii) भारत में सस्ता डेटा - मेरीमीकर संस्था रिपोर्ट के अनुसार भारत में $0.26/GB.

VisionIAS

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

डेटा उपलब्ध है जबकि वैश्विक औसत $0.34/GB है।

(iv) सूचना - संचार व सोशल मीडिया के माध्यम से एडटेक शिक्षा प्रणाली के बारे में जागरूकता।

(v) कम दरों पर गुणवत्ता युक्त शिक्षा की उपलब्धि।

(vi) पढ़ने में सुविधा व अनलिमिटेड देखने की सुविधा।

3. **एडटेक क्षेत्र के लाभ**

a. - शिक्षा का डेमोक्रेटाइजेशन होगा।

b. डिजिटल डिवाइड व इलिटरेसी में कमी होगी।

c. गुणवत्तायुक्त सस्ती शिक्षा की उपलब्धि से लर्निंग पॉवर्टी कम होगी।

d. SDG-4 - सतत विकास को बढ़ावा।

e. भारत की शिक्षा प्रणाली में ऑडियो-विजुअल प्रणाली का समावेशन होगा।

VisionIAS

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

एडटेक क्षेत्रक चुनौतियाँ

(क) बच्चों का स्वस्थ मानसिक विकास प्रभावित - स्क्रीन टाइम ↑ - UNESCO Report।

(ख) साइबर अटैक, साइबर जासूसी का खतरा।

(ग) एडटेक में फ्रॉड - फीस भुगतान के बाद पर्याप्त रिस्पांस नहीं मिल पाता।

(घ) गोपनीयता, व्यक्तिडेटा, डेटा सुरक्षा की चुनौतियाँ।

(ङ) बच्चों में स्कूली व क्लासरूम शिक्षा के लाभ नहीं मिल पाते है जिससे अकेलापन आता है।

(च) बच्चों की आँखों का कमजोर होना, चिड़चिड़ापन आदि।

अत: विनियमित एडटेक क्षेत्र शिक्षा में क्रांति ला सकता है इसीलिए NEP 2020 के अनुसार इस प्रणाली को जनोन्मुख बनाया जाये।

VisionIAS

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

18. Bring out the role of Accredited Social Health Activist (ASHA) workers in delivering health services in rural India. Also, suggest the measures that can be taken to overcome the challenges faced by them. **(250 words) 15**

ग्रामीण भारत में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा) की भूमिका पर प्रकाश डालिए। साथ ही, उनके द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों को दूर करने के उपाय भी सुझाइए।

भारत की 68% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है जबकि मात्र 31.4% सरकारी अस्पताल ग्रामीण क्षेत्रों में है वहीं मात्र 12.5% चिकित्सक सरकारी सेवा में है।

इसी परिदृश्य में ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में आशा वर्कर्स की भूमिका -

(i) ये सार्वजनिक स्वास्थ्य को इम्प्रूव करने में भूमिका -

a. कुपोषण को कम करने में - अभी विश्व के 30.4% कुपोषित बच्चे भारत में

b. एनीमिया - NFHS-V - 57% बच्चे व 68% महिलाएँ एनीमिया पीड़ित।

(ii) ये 'पोषण योद्धा' के रूप में सामुदायिक व

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

प्राथमिक तथा उपप्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर पोषण शिक्षा को प्रमोट कर सकती।

(iii) महिला स्वास्थ्य - अच्छा बच्चा सर्वे - भारत में महिला स्वास्थ्य सुधार में आशा कार्यकर्ता महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे।

a. सेनिटरी नेपकिन (pads) संबंधी जागरूकता।

b. प्रसवकाल संबंधी स्वास्थ्य में

c. संस्थागत प्रसव कराने में।

(iv) सरकारी स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं संबंधी जागरूकता - PM-मातृ वंदना, PM-मातृत्व व शिशु कल्याण योजना - लाभार्थी महिलाओं को राशि उपलब्ध कराने में।

(v) ये स्वास्थ्य सेवा संबंधी घर-घर सर्वे, आंगनवाड़ी में पोषण मान को बढ़ाकर 'ग्रामीण स्वास्थ्य प्रोफाइल' को अपडेट कर सकती।

VisionIAS

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

* आशा कार्यकर्ताओं द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियाँ -

(i) इन्हें पर्याप्त वेतन नहीं मिलता।

(ii) पर्याप्त चिकित्सकीय अवसंरचना के अभाव CHCs, PHCs पर इनकी दक्षता सीमित है।

(iii) सामाजिक चेतना विकास, जागरूकता, पोलियो दवाई वितरण में ग्रामीणों का सहयोग नहीं मिलता।

(iv) इनके पास सुदक्ष प्रशिक्षण का अभाव होता है।

अतः आशा कार्यकर्ता को सशक्त कर अति गरीबी, कुपोषण, एनीमिया, मातृ मृत्युदर, शिशु मृत्युदर से लड़ कर SDG-1, 2, 3, के पालन कर सकता है।

VisionIAS

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

19. Discuss the various concerns that have arisen for India after the Taliban takeover of Afghanistan. Also, suggest the measures that India should take in the given context. **(250 words) 15**

तालिबान द्वारा अफगानिस्तान पर अधिकार करने के बाद भारत के लिए उत्पन्न विभिन्न चिंताओं की विवेचना कीजिए। साथ ही, उन उपायों का सुझाव दीजिए जो इस संदर्भ में भारत द्वारा अपनाए जाने चाहिए।

भारत की 'पड़ोस प्रथम' नीति के तहत पड़ोसी देश अफगानिस्तान में 'August 2021 से तालिबान का शासन संचालित हो

तालिबानी शासन व भारत के लिए चिंताएँ

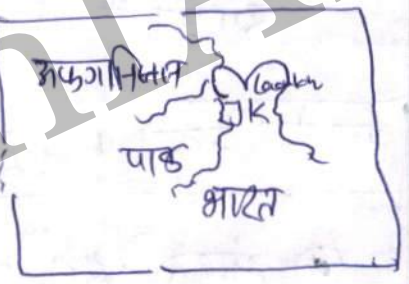

① राष्ट्रीय सुरक्षा - भारत के जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद को प्रमोट किया जा सकता।

ⓐ तालिबानी हक्कानी के नेटवर्क व पाक ISI के मध्य संबंधों का प्रभाव भारतीय सुरक्षा सूचना पर पड़ेगा।

ⓑ भारत में अलगाववाद, चरमपंथ व सांप्रदायिकता को प्रमोट कर अस्थिरता का प्रयास

VisionIAS

किया जा सकता है

(2) नार्को आतंकवाद -

भारत के पश्चिम में गोल्डन क्रिसेंट की उपस्थिति

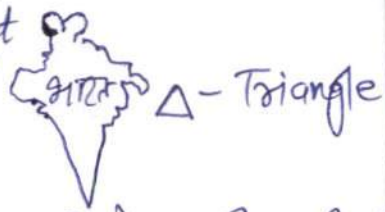

(a) हाल ही में अफगानिस्तान से गुजरात तट पर 3000 kg हीरोइन बरामद।

(b) भारत के पंजाब व J&K में ड्रग्स, अफीम की आपूर्ति व आतंकवाद का वित्तपोषण।

(3) भारतीय निवेश की सुरक्षा

(a) भारत ने $4 bn का निवेश किया है
- ज़रांज डेलाराम राजमार्ग, गारलैंड राजमार्ग
- सलमा बांध, संसद व काबुल स्टेडियम
- शहतूत बांध, स्कूल, अस्पताल

(b) भारत का ईरान में चाबहार बंदरगाह व चाबहार to ज़ाहेदान राजमार्ग

(c) INSTC कॉरीडोर की सुरक्षा

(4) आतंकवाद की समस्या - UN की हालिया रिपोर्ट

VisionIAS

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

अफगानिस्तान में जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा व इस्लामिक स्टेट तथा अलकायदा की उपस्थिति।

भारत के लिए उपाय

(i) भारत शांति प्रयासों से अफगान तालिबान के साथ राष्ट्रीय हितों के आधार पर वार्ता करें।

(ii) अफगान जनता को पर्याप्त सहायता- दालिया गेहूँ व आवश्यक वस्तु का निर्यात।

(iii) भारत ईरान के सहयोग से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की रक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास करें।

(iv) रूस के साथ सहयोग कर तालिबान के साथ वार्ता करें।

(v) भारत तालिबान के साथ आतंकवाद को न प्रमोट करने की शर्तों पर ही संबंध स्थापित करे।

अतः स्थानीय शांति, सुरक्षा, विकास के लिए भारत को शांति स्थापना के प्रयास करने चाहिए।

VisionIAS

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

20. Bangladesh is not only a key part of India's "Neighbourhood First policy" but also crucial for the "Act East policy". In this context, discuss the steps taken by the two countries to strengthen their relationship.

(250 words) 15

बांग्लादेश न केवल भारत की "नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी" का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि "एक्ट ईस्ट पॉलिसी" के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस संदर्भ में, दोनों देशों द्वारा अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए उठाए गए कदमों की विवेचना कीजिए।

भारत व बांग्लादेश द० एशिया में एक दूसरे के साथ सबसे लम्बी सीमा साझा (4096km) करते है तथा भारत का बांग्लादेश द० एशिया में सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है।

भारत की 'नेबरहुड फर्स्ट' तथा 'एक्ट ईस्ट नीति' के तहत भारत - बांग्लादेश संबंधों को मजबूत करने के लिए -

① आर्थिक स्तर पर -

- द्विपक्षीय व्यापार, 2009 में मात्र 2.7 bn अमेरिकी डॉलर
2021 - $11bn

द्विपक्षीय निवेश, भारत ने बांग्लादेश में $8 bn निवेश किया तथा 100 से अधिक

VisionIAS

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

भारतीय कंपनियाँ बांग्लादेश में कार्यरत।

(2) अवसंरचनात्मक स्तर:

- भारत ने रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र में निवेश किया
- बांग्लादेश भारत से 1200 MW ऊर्जा खरीदता है
- फेनी नदी पर मैत्री सेतु
- हल्दीबाड़ी से चिलाहाटी रेलवे लिंक प्रारंभ
- अखौरा अगरतला रेलवे प्रारंभ

(3) पीपल-पीपल संबंध

- इसके लिए 2015 में लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट किया - ~~99~~ 100 संविधान संशोधन अधि. 2015।
- भारत बांग्लादेश के वस्त्र क्षेत्र को भारतीय मार्केट में निवेश करने की अनुमति देता है

(4) आतंकवाद व उपद्रव

- शेख हसीना के प्रधानमंत्रित्व काल में पूर्वोत्तर क्षेत्र में शांति व्यवस्था को भंग करने

VisionIAS

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

वाले विद्रोही गुटों को दबाया गया।

(5) जलवायु परिवर्तन - इसके लिए दोनों देश मिलकर कार्य कर रहे हैं।

हालांकि कई चुनौतियों का समाधान भी आवश्यक है -

(i) नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) व प्रवासी लोगों का मुद्दा।

(ii) जल विवाद - तीस्ता नदी, तिपाईमुख बांध व फरक्का बैराज विवाद।

(iii) चीन का बढ़ता प्रभुत्व - चटगाँव पोर्ट पर

(iv) धार्मिक अतिरूढ़िवादिता की उपजती चिंगारी।

अतः 'पड़ोसी प्रथम' व 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' के तहत भारत व बांग्लादेश के मैत्रीपूर्ण संबंधों को प्रगाढ़ करने के लिए विद्यमान मुद्दों का समाधान आगामी प्रधानमंत्रियों की बैठक (Sept 2022) में किया जाना चाहिए।

VisionIAS